



1. डॉ० अजय कुमार पाण्डेय
2. जय प्रकाश शर्मा

21वीं सदी में भारत-पाकिस्तान संबंधों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कार्यकाल के सन्दर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

1. एसोसिएट प्रोफेसर- रक्षा एवं स्त्राजतिक, विभाग, 2. शोध अध्येता- रक्षा एवं स्त्राजतिक अध्ययन विभाग, श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया (उ०प्र०) भारत

Received-19.03.2024,

Revised-23.03.2024,

Accepted-29.03.2024

E-mail: aaryavart2013@gmail.com

सारांश: पाकिस्तान भारत के पड़ोसी मुल्क है। जिसकी लम्बाई 3323किमी (एल०ओ०सी) सीमा भारत के साथ लगता है। जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्यों से होकर गुजरता है। जो भारत का उत्तरी क्षेत्र पहाड़ीयों से घिरा है। हिमालय पर्वत शिखर के बीच से गुजरने वाला रास्ता रवैबर नाम से प्रसिद्ध है। भारत से निम्न पाँच नदियाँ यहा से गुजरती है। एवं पंजाब प्रान्त भूमि को उपजाऊ बनाता है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा उपस्थित है। एवं अफगानिस्तान की 86किमी की रेखा पाक अधिकृत कश्मीर से लगती है। दोनों राष्ट्रों का अभ्युदय एक साथ हुआ। देश-विदेश संबंधों के निर्माण में उसके राष्ट्रीय हित निर्णायक सिद्ध होते हैं। जिसका निर्माण भौगोलिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक व अन्तराष्ट्रीय घटना में निर्धारित है। जो पाकिस्तान नितियों का निर्धारण शुरू से किया और भारत की भावना सुरक्षा के साथ समानता, स्वयं का पहचान और इस्लामिक विचार धारा में अपना विदेश नीति बनाया जो कि भारत के अपने ब्रिटिश नीति में पाकिस्तान के भारत से अलग-अलग होने के पश्चात् वर्तमान समय तक भारत-पाकिस्तान के अच्छे पड़ोसी के रूप में माना, जो पाकिस्तान के द्वारा समय-समय पर विरोध किया गया एवं पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा भाई चारे के रूप में आपस में भारत का प्रयास रहा। भारत-पाकिस्तान के साथ असंलग्नता एवं गुटनिरपेक्षता को अपनाने पर बल दिया जो इसका मुख्य कारण रहा है।

कुंजीभूत शब्द- अन्तराष्ट्रीय सम्बंध, विदेश नीति, समाजिक सुरक्षा, आपसी व्यापार, अभ्युदय, निर्णायक, भौगोलिक, राजनीतिक।

15 अगस्त 1947 ब्रिटिश शासन के समाप्ति के पूर्व समय तक भारत का एक अभिन्न अंग था। स्वतंत्रता के बाद से भारत-पाकिस्तान सम्बंध संघर्ष से भरा हुआ है। राष्ट्र के कांग्रेस जिसने भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में संघर्ष नैतृत्व किया। एवं जोरदार तरीके से भारत के विभाजन का विरोध किया था। मुस्लिम लीग ने 'द्विराष्ट्र सिद्धांत' के आधार पर पाकिस्तान के आजादी के तुरन्त बाद से अनेक समस्या जैसे-सैन्य सम्पदा एवं वृत्तीय विभाजन दोनों देशों के बीच रेखा निर्धारण एवं राजघरानों द्वारा संचालित राज्यों का शामिल, अल्पसंख्यक के सुरक्षा सम्प्रदायिक मुद्दे, कश्मीर जल विवाद के रहते दोनों देशों के कुछ महत्वपूर्ण समझौता जो 1950 में नेहरू लियाकत के बीच समझौता, 1966 का तासकंद समझौता, 1972 का शिमला समझौता के आपसी मनमुटाव में कमी नहीं आया। और पाकिस्तान अपने सुरक्षा को ध्यान को देखते हुए भुट्टो कार्यकाल के परमाणु हथियार बनाने पर विचार किया और इस विचार को उजागर करके विदेशी सहायता लिया। और जियाउल हक ने भारत से वार्तालाप कर दौर रखा। जो कि समय-समय पर भारत विरोधी दुष्प्रचार और इस विचार को कश्मीर विवाद को अधिक ज्वलंत रखा।

परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल पाकिस्तान के राजनीति में काफी रोचक रहा है। पाक ने भारत की नीति में नई दिशा देने की कोशिश की। अतः कुटनीति में इन्होंने नये सम्बंध स्थापित करने के लिए प्रयास किये इन्होंने 1999 में पाकिस्तान ने तख्तापलट किया एवं सत्ता संभाला। मुशर्रफ ने भारत के प्रति दोहरी नीति अपनाया। जबकि भारत के लिए सहयोग की बात एवं दुसरी तरफ भारत को प्रोत्साहन भी किया। और अस्थिरता पैदा करते हुए कश्मीर आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी बताये तथा जिहादियों के आइ०एस०आई० के संरक्षण में रखते हुए दक्षिण एशिया ही नहीं जबकि समूचे संसार में आतंकवाद को बढ़ावा दिया। भारत के अनुरक्षण भावना को उजागर करके यानि सैनिक सामग्री एवं अमेरिका आर्थिक सहायता मुहैया करवाता रहा। जिसमें भारत से पाकिस्तान को 1995 में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया, जबकि भारत के अनुरोध के बावजूद मुशर्रफ ने एम०एफ०एन० का दर्जा नहीं दिया।

पाकिस्तान में सन् 2018 के पश्चात् दुबारा आम चुनाव हुए। जो नव निर्मित तहरीक-ए-इन्साफ को बहुमत हासिल हुआ। तहरीर-ए-इन्साफ में हिन्दी का वाक्य 'न्याय के लिए आन्दोलन' कहा जाता है। इस पार्टी का उद्घाटन सन् 1996 में पाकिस्तान क्रिकेटर से राजनीतिज्ञ बने इमरान खान द्वारा हुई। इस पार्टी ने पाक मुल्क में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभिमान किया जिसके कारण प्रहानमंत्री नवाज शरीफ को कुर्सी छोड़नी पड़ी।

इस तरह से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सात दशक के उपरान्त पाक लगभग 37 वर्षों की लम्बे अवधी तक सेना के साये में जिन्दा था। पाकिस्तान की सेना तीन धड़ों में सेना धार्मिक, गुट एवं राजनीति दलो के इर्द-गिर्द घुमता रहा।

भारत के मध्य एशिया का लंबे समय से काफी खर्चा रहा है। जिसका मुख्य कारण ऊर्जा क्षेत्र है। इन दिनों में भारत मध्य एशिया में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए पाकिस्तान के प्रभाव को न्यूनतम करने में लगा है। और वाह्य शक्तियों के इन क्षेत्रों में आन्तरिक खेल का आकार ले रहा है।

भारत अपना 4सी नीति में पाक को जोड़ने के साथ 4सी संचालन करने का प्रयास है। जिसमें 4सी का अर्थ (कार्य से कनेक्टिविटी, कम्युनिटी) के तहत प्रयास किया जाता है। भारत में ट्रैक-2 पहल में मध्य एशिया देशों एवं पाकिस्तान के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में जुन-2012 से ट्रैक-2 कूटनीति का पहल किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का कार्यकाल 2014 से लेकर अब तक:-हमारे देश में गठबंधन युग का अंत हुआ। तथा भारतीय जनता पार्टी को लगभग 30वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। नये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने विदेश नीति पर अपना ध्यान केन्द्रित किये और उन्होंने पड़ोसी देश एवं अन्य विदेशों में जाकर अपना संबंध मजबूत बनाने की पहल को आगे बढ़ाया।



पड़ोसी नीति के तहत प्रधानमंत्री जी के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह में दक्षेस सार्क के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री जी का प्रथम यात्रा भारत के छोटे पड़ोसी देश भूटान के लिए निर्धारित हुआ। वर्ष 2016 पाकिस्तान में भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यात्रा सम्पन्न हुई, यह यात्रा 12 वर्षों के बाद भारत के प्रधानमंत्री की पाकिस्तान यात्रा की गयी तथा इससे प्रतीत हुआ कि भारत-पाकिस्तान संबंध बनाये रखना कितना गंभीर रहा है।

जबकि प्रधानमंत्री जी के यात्रा के पश्चात् पंजाब प्रांत के पठानकोट जनपद स्थित एयर फोर्स स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ। जिसमें जैस-ए-मोहम्मद संगठन का हाथ बताया गया और हमले के बाद पूर्ण रूप से भारत-पाक के वार्ता पर विराम लग गया। जिसमें पाक 2016 के मध्य में कश्मीर में आकर-हिंसा का अंजाम दिया। जबकि ईरान-पाक सीमा पर आत्मघाती हमला हुआ। जिसमें मोदी सरकार द्वारा शुरु की गयी शांति प्रक्रिया प्रभावित हुआ। इस क्रिया-प्रतिक्रिया में दोनों देशों को विश्वास को लेकर आपस में मतभेद हुआ। जबकि सन् 1973 के बाद पहली बार भारत द्वारा बालाकोट पाकिस्तान में आतंकवादियों को बम से नष्ट कर दिया गया और इस प्रकार भारत-पाक की आपसी पड़ोसी संबंध में अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो गई और वर्तमान समय तक देखने को मिल रहा है। एक्ट ईस्ट पालिसी:- प्रधानमंत्री जी के दुसरे कार्याकाल में दोनों देशों के बीच शांति बेउम्मीद से कायम हुआ। जो कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद दोनों देशों में कुटनीतिक संबंध खत्म हो गया। 2019 के अंत में करतारपुर गलियारे को खोले जाने के बाद सकारात्मक संकेत देने का प्रयास पाकिस्तान द्वारा किया गया था। जिसमें सिख समुदाय के लोग यात्रा कर सकें। दोनों देशों के बीच यह शांति का गलियारा परस्पर समझौता द्वारा हुए। तथा दोनों देशों के बीच सम्प्रभुता का एक दुसरे के प्रति सम्मान करना है।

भारत ने बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिव (बी0आर0आई) को प्रमुख परियोजना चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सी0पी0ई0सी0) को लेकर चीन विरोध किया है। क्योंकि भारत इस आर्थिक गलियारे के निर्माण कार्य को अवैध मानता है। वास्तव में सी0पी0ई0सी0 परियोजना ने भारत-पाकिस्तान के तनाव को बढ़ा दिया। भारत की सबसे ज्यादा आपत्ति गिलगिट-बाल्टिस्तान से निर्मित होने वाली परियोजना से है। जो हमारे देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता के लिये चुनौती बन गया है।

भारतीय सीमा प्रांत कश्मीर, लद्दाख, अरुणांचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखण्ड और पंजाब की सीमाओं के पास चौवालिस पुल बनाया जा रहा है। जिससे सैनिकों की सुचारु रूप से हथियार मुहैया करवा सकें। वर्तमान में पाकिस्तान के लोकतांत्रिक सरकार है। जो आन्तरिक अस्थिरता, बाहरी दबाव, भारत की समानता एवं प्रतिस्पर्धा की भावनाएं एवं मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण भारत के साथ मधुर संबंध स्थापित नहीं है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाहते हैं। जो तीन प्रमुख 'ए' आर्मी, अल्लाह, आई0एस0आई0 वहा की राजनीति को तय करता है। तथा पाकिस्तान आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान द्वारा बलुचिस्तान, पख्तुनिस्तान, मुजाहिर की समस्या को लेकर संकट से जूझ रहा है। जिन्हे दबाये रखने के लिए 2 16 2 लाख सैनिक लगाने पड़े हैं।

निष्कर्ष:-हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ब्रिटिश नीति में पहले पड़ोस नीति को अपनाया है। जिसमें पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मिलकर मजबूत रिश्ते बनाना काफी महत्वपूर्ण रहा है। वर्तमान में पाकिस्तान सरकार को चाहिए कि वह इन रिश्तों को मिठास में भरकर अपने आगे के कदम को बढ़ाते हुए भारत के साथ मजबूत संबंध स्थापित करें और विदेश नीति में साथ ही साथ बदलाव लाये। जिस प्रकार वर्तमान सरकार ने कश्मीर के मुद्दे की शान्तिपूर्ण तरीके से उसको समाप्ति का प्रयास किया। ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान को पहल करने की आवश्यकता की जरूरत है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. दीक्षिति, जे0एन0 "भारत-पाकिस्तान संबंध" (युद्ध और शान्ति में), प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003।
2. वर्मा, डा0 दीननाथ, "आन्तराष्ट्रीय संबंध", ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2000।
3. सरकार, भास्कर, "कारगिल वार: पोस्ट प्रजेक्ट एण्ड फ्यूचर" कैसर पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 2010।
4. खान, एम0ए0, "फस्ट राउंड इंडो पाक-वार 1965" विकाश पब्लिकेशन, गाजियाबाद, 1979।
5. दत्त, संजय, "वार एण्ड पीस इन कारगिल सेक्टर", ए0पी0एच0 पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 2000।
6. भार्गवा, जी0एस0 "पाकिस्तान इन क्राइसिस", विकास पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 2006।
7. चन्द्र, प्रकाश: "पाकिस्तान: पास्ट एण्ड प्रजेन्ट, ए0पी0एच0 पब्लिकेशन कारपोरेशन, नई दिल्ली, 2003।
8. दीक्षित, जे0एन0: भारत की विदेश नीति और आतंकवाद, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2006।
9. खान, वसीम अहमद: भारत-चीन-पाकिस्तान संबंध, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1998।
10. नैयर कुलदीप: वाल एट बाघा: इण्डिया पाकिस्तान रिलेशन, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2005।
